



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, २१ अगस्त, १९९३/३० भाद्रपद, १९१५

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला २५ मार्च, १९९२

सं० एल एल० आर (राजभाषा) (बी) (१६)-७/९१.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, १९८१ (१९८१ का १२) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “दि हिमाचल प्रदेश भूदान योजना ऐक्ट, १९७७ (१९७८ का २९)” के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा

रूपान्तर को एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो तो यह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-

सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1977

(1978 का 29)

(31-8-1991 का अध्याय विधान)

श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरम्भ किए गए भूदान यज्ञ के सम्बन्ध में क्रिया-कलापों का सुचारु चलाने, भूदान यज्ञ बोर्ड का गठन करने, उनके बोर्ड की भूमि का सदान करने, सदान में प्राप्त भूमि का भूमिहीन व्यक्तियों में वितरण करने तथा उनका सामुदायिक प्रयोजनों और उपयोगी कामों में सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अठ्ठाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह एक्ट द्वारा अधिनियमित किया जाता है:—

अध्याय-1

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1977 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है:

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न परिभाषाएं हो:—

(क) "भूदान यज्ञ" से श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा बोर्ड के पक्ष में स्वीकृत दाव के माध्यम से भूमि के अर्जन के लिए आरम्भ किया गया आन्दोलन अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन स्थापित भूदान यज्ञ बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "सामुदायिक प्रयोजन" से ऐसा प्रयोजन अभिप्रेत है जो माध्यामिक तौर पर गांव के समुदाय की भलाई के लिए है;

(घ) "भूमिहीन व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास कोई भूमि नहीं है या स्वामी, पट्टेदार अथवा अभिधारी की हैमियत में एक एकड़ से कम भूमि है;

(ङ) "राज्य अधिकारी" हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) के अधीन, नियुक्त किया गया राजस्व अधिकारी और अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन राज्य अधिकारी के कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया जाए;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

- (छ) ऐसे अन्य सब शब्दों और पदों के जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु उसमें परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश अधिपति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) के अधीन क्रमशः उनके हैं।

अध्याय-2

भूदान यज्ञ
बोर्ड की
स्थापना,
निर्गमन
और कर्तव्य।

3. (1) हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम से एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

(2) बोर्ड एक निर्गमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे जंगल और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति को सज्जित और व्यय करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उसका विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) बोर्ड का, भूदान यज्ञ के फायदे के लिए उसमें निहित समस्त भूमि को, इस अधिनियम के उपबन्धों और उद्घीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रशासित करना, कर्तव्य होगा।

बोर्ड का
गठन।

4(1) बोर्ड का गठन अध्यक्ष और सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट चार या अधिक परन्तु आठ से अधिक सदस्यों से होगा।

(2) अध्यक्ष और सदस्यों के नाम निर्देशन या नियुक्ति की राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और पुनः नियुक्ति या पुनः नाम-निर्देशन के लिए पात्र होंगे :

परन्तु बोर्ड का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, किसी भी समय राज्य सरकार की अपना त्यागपत्र लिखित रूप में प्रस्तुत करके पद त्याग सकेगा, किन्तु ऐसा कोई त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता है :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, जो राज्य सरकार की राय में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है या असमर्थ है, अथवा जिसने अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने पद का लोक हितों के लिए हानिकार रूप में दुरुपयोग किया है, पद से हटा सकेगी।

(4) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों और कृत्यों का धारा 30 के अधीन निनिर्वाह बनाने की शक्ति के सिवाय, किसी सदस्य या अपने में से तीन या अधिक सदस्यों की उस नमिति को, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

5 (1) यदि राज्य सरकार का किसी समय समाधान हो जाता है कि:-

बोर्ड का विघटन।

- (क) बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित या समनुदेशित कर्तव्यों के निर्वहन या कृत्यों के अनुपालन करने में युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना असफल रहा है;
- (ख) ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि बोर्ड इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित या समनुदेशित कर्तव्यों के निर्वहन या कृत्यों के अनुपालन करने में असमर्थ हो गया है या असमर्थ हो जाएगा; या
- (ग) बोर्ड को विघटित करना अन्यथा समीचीन या आवश्यक है, तो यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा:-

- (i) बोर्ड को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विघटित कर सकेगी;
- (ii) इस अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड के पुनर्गठन का निर्देश दे सकेगी; और
- (iii) घोषणा कर सकेगी कि उस अवधि के लिए जिसके लिए इस विघटित किया गया है, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन, प्रयोग और अनुपालन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा ऐसे निबन्धनों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जैसे उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए ऐसे अनुसंगिक और पारिभाषिक उपबन्ध बना सकती जो इसे आवश्यक प्रतीत हो।

6. बोर्ड में निक्तियों को भरने का ढंग, उसके कार्यकरण और काम-बाज के संचालन प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

बोर्ड में निक्तियाँ।

7. इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही, बोर्ड में विद्यमान किसी व्यक्ति या बोर्ड के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के नावनिर्देशन में किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण प्रश्नगत नहीं होगी।

कार्यवाहियों को विधिमाम्यता।

8. बोर्ड, विहित रीति में, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जिन्हें वह उनके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक समझे।

अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति।

9. बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की पारिश्रमिक और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनियमों द्वारा अवधारित की जाएगी।

अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें।

10. बोर्ड की अपनी निधि होगी और वह केन्द्रीय या राज्य सरकारों अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निवास से, चाहे वह निमित्त हो या नहीं, इस अधिनियम के सभी या उनमें से किसी प्रयोजनों के लिए अनुदान संदान या दान ग्रहण स्वीकार कर सकेगा।

बोर्ड की निधि।

निधियों का उपयोगन। 11. बोर्ड में निहित सभी सम्पत्ति, निधि और अन्य आस्तियां इस द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार धारित और उपयोगित की जाएंगी।

तहसील समितियां। 12. (1) बोर्ड किसी तहसील के लिए जहां यह ऐसा करना आवश्यक समझे बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए तीन से अत्यधिक सदस्यों से गठित तहसील समिति का गठन कर सकेगा।

(2) तहसील समिति, किसी सदस्य या अपने तीन या अधिक सदस्यों की उप समिति को, इस अधिनियम के अधीन, अपनी किन्हीं शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगी।

अध्याय-3

भूदान यज्ञ की भूमि का संदान 13. (1) तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो भूमि में अन्तर्णीय हित रखता हो, ऐसी भूमि का इस सम्बन्ध में विहित रीति से एक लिखित घोषणा द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् भू-दान घोषणा कहा गया है) "भूदान यज्ञ" को संदान और अनुदान कर सकेगा।

(2) भूदान घोषणा, इसके करने के बाद, यथाशीघ्र, बोर्ड के पाम दाखिल की जाएगी :

परन्तु यदि भूदान घोषणा में वर्णित भूमि का बाजारकीमत के आधार पर विहित रीति में संगणित मूल्य पचास हजार रुपये या उससे अधिक बनता हो, तो भूदान घोषणा को तब तक स्वीकार्य नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसी भूमि का दाता, आधिकार अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस याज्ञ का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि ऐसे दाता से आधिकार या इसकी बकाया के रूप में, ऐसी घोषणा करने के दिन, कुछ देय नहीं था।

(3) बोर्ड, यदि यह दान को स्वीकार्य समझता हो, तो घोषणा को उस तहसील में अधिकारिता रखने वाले राजस्व अधिकारी को भेजेगा, जिसमें भूमि स्थित है।

(4) उप-धारा (1) में उल्लिखित घोषणा प्राप्त होने पर यदि राजस्व अधिकारी का ऐसी आंच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाता है कि दाता दान करने में सक्षम है और भूमि में विधिमानी हक रखता है, वह ऐसे व्यक्तियों को जिनको वह भूमि में हित रखने वाला समझता हो, विहित प्रारूप में, नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व यह कारण दर्शित करने का नोटिस जारी करेगा कि दान को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(5) राजस्व अधिकारी उप-धारा (4) में निर्दिष्ट नोटिस की प्रति अपने न्यायालय के नोट्स बोर्ड पर भी चिपकाएगा और इसे उस गांव में, जहां भूमि स्थित है, डोंडो पिटवा कर प्रकाशित करवाएगा।

(6) सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति, नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, राजस्व अधिकारी के समक्ष यह कारण दर्शाते हुए कि दान को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, आक्षेप दाखिल कर सकेगा।

(7) ऐसे सभी आक्षेपों की जांच और वनिश्चय राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(8) यदि विनिदिष्ट तारीख से पूर्व कोई भी आक्षेप दाखिल नहीं किया जाता है; या यदि दाखिल किए गए सभी आक्षेपों को राजस्व अधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो; तो वह बोर्ड की ओर से दान को स्वीकृत करने का आदेश पारित करेगा।

(9) दान की स्वीकृति पर, भूमि में दाता के सभी हक और हित निर्विवादित हो जाएंगे और भूमि उन्हीं अधिकारों में जिनमें यह दाता द्वारा धारित थी, बोर्ड में निहित होगी।

(10) राजस्व अधिकारी, कार्यवाहियों के किसी स्तर पर निम्नलिखित आक्षेपों में से किसी पर दाता के प्रस्ताव को खारिज कर मकेगा, अर्थात् :--

- (i) कि दाता दान देने को अक्षम है ;
- (ii) कि दाता का हक त्रुटिपूर्ण है ;
- (iii) कि भूमि पर बिलगम है ; और
- (iv) ऐसे अन्य आधार जो कि विहित किए जाएं।

14. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, कोई भी स्वामी निम्नलिखित प्रकार की भूमि का संदान करने के लिए सक्षम नहीं होगा :--

भूमि जिस-
का संदान
नहीं किया
जा सकेगा।

- (क) चरागाह शबदाह या कब्रस्थान भूमि, टैंक, पथ या खलिहान के रूप में अभिलिखित या प्रथा द्वारा मानी गई भूमि ; और
- (ख) ऐसी अन्य भूमि जिसको राज्य सरकार राजपत्र में अधिमूचना द्वारा, विनिदिष्ट करे।

(2) किसी जीवनपर्यन्त सम्पदा का धारक उसमें से केवल अपने आजीवन हित का ही संदान करने के लिए सक्षम होगा।

15. (1) जहाँ कोई भूमि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व भूदान यज्ञ के प्रयोजनों के लिए संदान की गई है वहाँ बोर्ड ऐसी समस्त भूमि को एक सूची उसमें निम्नलिखित दर्शाते हुए तैयार करेगा :--

इस अधि-
नियम के
प्रारम्भ से
पूर्व संदान
की गई
भूमि।

- (क) क्षेत्र और विवरण ;
- (ख) दाता का नाम ;
- (ग) भूमि में दाता के हित की प्रकृति ;
- (घ) यदि भूदान यज्ञ के अनुहरण में किसी व्यक्ति को भूमि अनुवत्त कर दी गई है तो उस व्यक्ति का नाम जिसको भूमि अनुवत्त की गई है ;
- (ङ) खण्ड (घ) के अधीन अनुदान की तारीख ; और
- (च) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जाएं।

(2) इस प्रकार तैयार की गई भूची उस जिले के उपायुक्त को भेजी जाएगी जिसकी अधिकारिता में भूमि स्थित है।

(3) ऐसी भूची प्राप्त होने पर उपायुक्त उस भूची में वर्णित भूमि के बारे में धारा 13 के अनुसार कार्रवाई करवाएगा।

(4) धारा 13 से 18 तक के उपबन्ध उक्त भूमियों के समस्त संदानों के बारे में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किए गए भूमि के समस्त संदानों के बारे में लागू होते हैं।

परन्तु जहां राजस्व अधिकारी द्वारा धारा 13 की उप-धारा (7) के अधीन आदेश किया जाए, वहां दान उसी तारीख से ही स्वीकार किया गया समझा जाएगा जिसकी भूमि का संदान किया गया था और इन प्रयोजन के लिए यह अधिनियम ऐसी तारीख को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(5) यदि कोई भूमि जिसका संदान इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्राप्त किया गया था भूदान यज्ञ के अनुसरण में पहले ही किसी व्यक्ति को अनुदान कर दी गई हो तो वह बोर्ड द्वारा ऐसे व्यक्ति को उसी तारीख से अनुदान की गई समझी जाएगी जिसको ऐसा व्यक्ति उसका कब्जा लेता है और अनुदान उन सभी दायित्वों के अधीन होगा जिसके अधीन बोर्ड द्वारा दिया गया अनुदान साधारणतया होगा।

(6) किसी विधि में प्रतिकूल उपबन्धों के होते हुए भी राज्य सरकार से सीधे भूमि धारण करने वाला अभिधारी, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि में अन्तरणीय हित का स्वामित्व रखने वाला समझा जाएगा।

घोषणा का
अप्रति-
संस्मरणीय
होना।

16. भूमि का प्रत्येक दान, जिसके बारे में धारा 13 के अधीन आदेश पारित किया जा चुका है आदेश की तारीख के पश्चात् अप्रतिस्मरणीय होगा।

बोर्ड में
निहित
भूमि का
कुर्सी योग्य
न होना।

17. बोर्ड में निहित भूमि, बोर्ड के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री या आदेश के निष्पादन में, कुर्सी या विक्रय के दायित्वाधीन नहीं होगी।

अध्याय-4

भूमि का वितरण

भूमिहीन
व्यक्तियों
को भूमि का
अनुदान।

18. बोर्ड या ऐसा अन्य प्राधिकारी अथवा व्यक्ति जिसे बोर्ड राज्य सरकार के अनुमोदन से, साधारणतया या किसी क्षेत्र के बारे में विनिर्दिष्ट कर, विहित रीति से इसमें निहित भूमि को भूमिहीन व्यक्ति को अनुदान करेगा और आर्बिट्रि का ऐसी भूमि में, इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के विवाण, कोई अधिकार नहीं होगा और

न हो किन्ना अधिकार के लिए दिया करने का अधिकार होगा :

परन्तु बोर्ड में निर्दिष्ट और इस धारा के अधीन विवरण के लिए विहित भूमि के पाचवें भाग में अन्योन को अनुमोचन करने में सम्बन्ध अपने अपने व्यक्तियों में निर्धारित किया जाएगा और ऐसी भूमि के बाँटने भाग में अन्योन को अनुमोचन करने में सम्बन्ध अपने अपने व्यक्तियों में निर्धारित किया जाएगा।

19. यद्यपि अनुदान, अस्त-रूप और आबंटन, जैसा भी लागू हो, भूदान यज्ञ के प्रयोजन के अनुसार किया जाएगा।

भूदान यज्ञ के प्रयोजन के लिए अनुदान, अस्त-रूप और आबंटन।

अध्याय-5

प्रकीर्ण

20. तत्कालीन प्रकृतः किसी विधि में किसी घात के प्रतिकूल होते हुए भी, धारा 13 के अधीन स्वीकार्य बात या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किए गए या किए हुए समझ गए भूमि अनुदान को निम्नलिखित में छूट होगी और यदि छूट समझी जाएगी :—

स्टाम्प-शुल्क और रजिस्ट्री-करण से छूट।

(क) स्टाम्प शुल्क के संदर्भ ; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण और दस्तावेजों के निष्पादन सम्बन्धी विधि के अधीन रजिस्ट्री-करण या अनुप्रमाणन।

21. (1) राज्य सरकार, यदि इसको समाधान हो जाता है कि बोर्ड किसी वर्ष में भूमि का अनुदान करने में समर्थ नहीं हुआ है, उसे वर्ष के लिए उस भूमि पर देय भू-राजस्व या लगान माफ कर सकेगी।

भू-राजस्व माफ करने की शक्ति।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि उप-धारा (1) के अधीन इशारी प्रदत्त शक्तियाँ, एसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो निर्दिष्ट की जाएँ, किसी अधिकारी द्वारा, जो उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रयोग की जा सकेंगी।

22. यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 18 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवंटित की गई है,—

आबंटित की बेदखल करने की शक्ति।

(i) किन्हीं निबन्धनों और शर्तों की, जिनके अधीन आबंटन किया गया है, पालन करता है ; या

(ii) कोई ऐसी सूचना देता है जो कि निरुद्ध है या वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वह सत्य नहीं है ; या

(iii) उसके आवंटित भूमि के बारे में, किसी देय को संयत्न करने में असफल रहता है ; या

- (iv) ऐसी भूमि को पर्याप्त हेतु के बिना (यदि भूमि खेती करने के प्रयोजनों के लिए आवंटित की गई हो) दो क्रमवर्ती वर्षों में खेती करने में असफल रहता है ; या
- (v) आवंटन की अवधि के अवसान के पश्चात्, भूमि का कब्जा, व्यवस्थिति बोर्ड या ग्राम सभा को परिदत्त करने में असफल रहता है ;
तो बोर्ड आवंटन को रद्द करने के लिए विहित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा और तदुपरि विहित प्राधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात्, जो यह ठीक समझे, करने और आवंटित को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवंटन को रद्द कर सकेगा और आवंटित या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में भूमि पाई जाए, बेदखल करने के पश्चात् भूमि का कब्जा बोर्ड को, प्रत्यावर्तित कर सकेगा :

परन्तु इस धारा के खण्ड (ii) के अधीन उल्लिखित आधारों पर आवंटित की बेदखली की दशा में, ऐसा आवंटित उसकी आवंटित की गई भूमि के बारे में पचास रुपए प्रति बीघा की दर से आंशिक लगान संदत्त करने का भी दायी होगा और ऐसा लगान भू-राजस्व को बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

नियम
बनाने की
शक्ति।

23. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी:—

- (क) धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन भूमि दान को घोषणा प्रस्तुत करने के लिए घोषणा का प्ररूप विहित करने ;
- (ख) धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन व्यक्तियों से यह कारण बताने के लिए कि भूमि के दान को क्यों स्वीकार न किया जाना चाहिए, की अपेक्षा करने वाले नोटिस का प्ररूप विहित करना ;
- (ग) धारा 13 की उप-धारा (10) की मद् (i) के अधीन दान करने के प्रस्ताव को नामंजूर करने के लिए अन्य आधारों का कथन करना ;
- (घ) धारा 15 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन अन्य विधित्तियों विहित करना ;
- (ङ) धारा 30 के अधीन बोर्ड द्वारा उप-विधियां बनाने के लिए प्रक्रिया विहित करना ; और
- (च) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आंशिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया है, या पूर्वोक्त सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिस्थित रूप में ही प्रभावी

होगा। यदि उक्त अवधान से पूर्व विधान भंग महसूस हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु, नियम के ऐसे परिचित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात को विधिवानुसृत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

24. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई पैदा होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती (जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों) जो इसे कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

25. धारा 22 के अधीन पारित किए गए आदेश की तारीख की भूमि पर कब्जा रखने वाला कोई व्यक्ति और कोई व्यक्ति, जो विधि के अनुसार से अन्यथा भूदान यज्ञ के प्रयोजनों के लिए संदान में प्राप्त भूमि का कब्जा लेता है, बोर्ड या सम्बन्धित आर्बिटरी द्वारा राज्य अधिकारी को आवेदन करने पर वेदवली दिया जा सकेगा। ऐसी वेदवली के लिए हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) की धारा 163 के उपबन्ध लागू होंगे।

विधिविरुद्ध कब्जा रखने वाले व्यक्तियों की वेदवली।

26(1) यदि बोर्ड को दान की गई भूमि किसी धृति का भाग है तो बोर्ड या सम्बन्धित आर्बिटरी राज्य अधिकारी को कब्जे के लिए आवेदन कर सकेगा और राज्य अधिकारी किसी विधि में प्रतिकूल बात को हांते हुए भी, धृति का विभाजन और भूमि का सीमांकन कर सकेगा तथा, यथास्थिति, लगान या भू-राजस्व को प्रभावित कर सकेगा।

धृतियों का विभाजन।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन विभाजित धृति पर, यथास्थिति, लगान या राजस्व की कोई बकाया है तो राज्य अधिकारी, बोर्ड को दान की गई धृति के भाग पर दाय अधिकारी बकायों के भाग को अवधारित करेगा और तदुपरि बोर्ड और आर्बिटरी इस प्रकार अवधारित बकाया के भाग को संदत्त करने के लिए दायी होंगे और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1953 (1954 का 6) में किसी बात को हांते हुए भी बोर्ड या आर्बिटरी धृति के शेष भाग के बारे में बकाया के लिए दायी नहीं होंगे।

27. बोर्ड ऐसी सभी संविदाएं और उनका पालन कर सकेगा जिनको यह इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, आवश्यक या समीचीन समझे

संविदाएं करने की शक्ति।

28. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य अधिकारी या किसी प्राधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् की गई कार्रवाई या पारित आदेश किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत नहीं होगा।

सिविल न्यायालयों की अधिकांश वार्जन।

29. इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियां, सभी प्रयोजनों के लिए, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) के अधीन की कार्यवाहियां समझी जाएंगी, और उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को लागू होने वाली प्रक्रिया का राज्य अधिकारी द्वारा अनुसरण किया जाएगा।

प्रक्रिया।

उप-विधियों
यान की
शक्ति। 30 राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, बोर्ड रा जपल में अधिभूत ना
द्वारा, इस पर इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के
लिए, या उससे अनुपूरक या आनुवंशिक मागने के बारे में विनियम बना सकेंगे और
इस प्रकार बनाई गई उप-विधियाँ बोर्ड द्वारा विहित रीति में प्रकाशित की जाएंगी।

निरसन
और व्या-
वृत्तियाँ। 31. (1) प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में सन्निविष्ट क्षेत्रों
में यथा लागू हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 (1955 का 2), पंजाब
पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश
में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दी पंजाब भूदान यज्ञ ऐक्ट, 1955 (1956 का 45)
और हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अध्यादेश, 1977 (1977 का 5) का एतद्द्वारा निरसन
किया जाता है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निरसित अधिनियमों और अध्यादेश के उपबन्धों
द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात, कारवाई,
परिदत्त और वितरित की गई भूमि, स्थापित किया गया बोर्ड, बनाए गए नियम और
जारी की गई अधिसूचनाएँ उस विस्तार तक जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से
संगत हों, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
की गई परिदत्त वितरित स्थापित बनाए गए या जारी की गई सगुनी जाएंगी मानें।
यह अधिनियम उस दिन जब ऐसी चीज ऐसी कारवाई की गई, भूमि परिदत्त और
वितरित, बोर्ड स्थापित, नियम बनाए या अधिसूचनाएँ जारी की गई थी प्रवृत्त था।